SHRI G.G. SWELL : All right.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Yes, Mr. Pramod Mahajan.

---

## HALF-AN-HOUR DISCUSSION on points Arising out of Answer gievn on the 2nd March 1993 to Starred Question 103 regarding revamping of procedure for recovery of Income-tax.

**श्री प्रमोद महाजन** (महाराष्ट्र) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा का अर्थ हम सभी जानते हैं। जब प्रश्नोत्तर काल में किसी एक प्रश्न का उत्तर आधा-अधूरा होता है तो उसकी व्यापक चर्चा हेतु अध्यक्ष जी इस आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देते हैं। मैं आशा करता हूं कि वित्त राज्य मंत्री भी इस अर्थ को जानते होंगे और दो मार्च को, लगभग दो माह पूर्व, तारांकित प्रश्न संख्या 103 की चर्चा पढ़कर आए होंगे और उसके आधार पर आज विस्तृत उत्तर देंगे।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 नवम्बर, 1992 को निगम कर सहित आयकर का कुल बकाया अनुमानित 6,517 करोड़ रुपए था। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस अनुमान का आधार क्या है ? क्योंकि समाचार पत्रों में यह खबरें छपी हैं कि मुम्बई के शेयर बाजार के कुछ दलालों से 8,000, 9,000, 10,000 करोड़ रुपया आयकर का आना है और इस प्रकार की सूचनाएं उनको भेजी हैं। तो यह जो अनुमानित 6,517 करोड़ रुपए का आंकड़ा उस दिन उत्तर में दिया गया था, इसकी वास्तविकता क्या है ?

यह आंकड़ा कैसे इकट्ठा किया जाता है, और जो लोग जैसा मैंने कहा कि जिनको नोटिस दी जाती है, क्या इससे उनको निकालकर यह आंकड़ा है और इसलिए मैं सबसे पहले यह स्पष्टीकरण जानना चाहूंगा कि यह 6,517 करोड़ रुपये का आंकड़ा आपने कैसे तय किया है, इसके मोटे रूप से किस प्रकार के निकट हैं। उप-सभाध्यक्ष जी, इस बकाए को वसूल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती और इसके लिए सभी सहमत होंगे। मुझे कभी-कभी यह लगता है कि कर का न देना यह धीरे-धीरे, मुझे शब्द के लिए क्षमा करें, कि हमारा यह राष्ट्रीय स्वभाव बनने की स्थिति में हम जा रहे हैं और अगर इस प्रकार का राष्ट्रीय स्वभाव होगा और अगर नागरिक किसी भी कारण से सरकार को कर नहीं देगा तो सारी व्यवस्था जिस आधार पर खड़ी है, वह व्यवस्था टूट जाएगी और इसलिए इस बकाए को वसूल करना चाहिए, इसके संबंध में किसी प्रकार की दो राय हो नहीं सकती और इसमें सरकार जिस सख्ती से कदम लेना चाहे, मुझे लगता है कि इसमें सदन सरकार के साथ रहेगा और उनको इस वसूली में जिस प्रकार की भी सहायता हो, वह जरूर करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से जनता में एक आम धारणा है कि आयकर की वसूली में छोटों के लिए तो बड़ी गरमी होती है लेकिन जो बड़े हैं, उनके संबंध में आयकर विभाग नरमी का रुख अपना लेता है और इसलिए दो मार्च की चर्चा में यह प्रश्न बार-बार उठा था कि जिन पर सर्वाधिक आय कर का बकाया है, ऐसे पहले दस बकाएदारों के नाम क्या हैं ? उस दिन तो वित्त राज्य मंत्री जी ने यह कह कर बचाव कर लिया कि मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। आज मुझे विश्वास है, क्योंकि दो मार्च के बाद चर्चा हो रही है, वित्त राज्य मंत्री इन दस लोगों के नाम लेकर आए होंगे। मुझे नाम में रूचि है, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। लेकिन अगर देश को पता चले कि वह पहले दस कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने आय कर का बकाया नहीं दिया है, तो मैं मंत्री जी से इसमें दूसरा प्रश्न करना चाहूंगा कि वह पहले कौनसे दस व्यक्ति हैं जिनसे सर्वाधिक आयकर आना है और उनसे यह कब से आना है और उनके प्रति आज तक सरकार ने किस प्रकार की कार्रवाई की है और उसका क्या फल निकला है ? व्यक्तियों के साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि वह पहली दस कंपनियां कौन सी हैं,

क्योंकि जैसे व्यक्तिगत रूप में बकाएदार हो सकते हैं, वैसे कम्पनी के रूप में भी बकाएदार हो सकते हैं। तो वह पहली दस कंपनियां कौन सी हैं जो आयकर के बकाएदारों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके पास सबसे अधिक बकाया है और इन कंपनियों के विरोध में यह आय कर वसूलने की दृष्टि में सरकार ने किस प्रकार की कार्रवाई की है ?

मैं आगे जाकर यह कहना चाहता हूं कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्यक्ष कर की वसूली में न्यायालयों में मुकदमेबाजी में सारा पैसा सदियों तक अटका रहता है। प्रत्यक्ष कर की वसूली और सरकार की तिजोरी के बीच में यह मुकदमें शुक्राचार्य की आंख की तरह हमेशा इसको रोके रखते हैं, अटका कर रखते हैं और इसलिए इन मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार यह कहती हैं कि राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायालय की स्थापना की आवश्यकता है, क्योंकि साधारण दृष्टि से अगर मुकदमा लेकर न्यायालय में जाएं, सरकार वसूल करने की मंशा रखती भी है और सरकार बड़े लोगों से लेना चाहती भी हो, तो जब हम मुकदमा लेकर न्यायालय में जाते हैं तो न्याय तो बहुत देरी से मिलता है लेकिन तारीखें एक के बाद एक तुरन्त मिलती जाती हैं और इस पृष्ठिभूमि में मैं यह जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायालय का सरकार का बिचार है, इस दिशा में सरकार भी विचार कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य से उक्ति और कृति में अंतर है और इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायालय की स्थापना कब की जाएगी, इसका कानून कब बनेगा, इस संबंध में आप संसद के समक्ष कब आएंगे और हम यह चाहते हैं कि शीघ्रताशीघ्र राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायालय बने और इस न्यायालय के द्वारा जो लोग सरकार का पैसा नहीं देते हैं उन पर तुरन्त कार्रवाई हो सके, इस दृष्टि में आप क्या कर रहे हैं ? मेरा अगला छोटा सा सवाल है कि जो आयकर अधिनियम 1961 है, क्या सरकार यह नहीं मानती कि इस अधिनियम में अनगिनत चोर रास्ते हैं ? क्या सरकार 1961 के इस आयकर अधिनियम को पर्याप्त मानती है और यदि पर्याप्त मानती है तो क्या सरकार इस अधिनियम की दृष्टि से जिसके कारण बकाया न हो, इसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन करने का विचार रखती है ? मुझे कृपया यह उत्तर न दें कि इस अधिनियम में बदल करते रहना, यह निरंतर प्रक्रिया है और जैसे-जैसे समस्याएं आती हैं वैसे-वैसे हम उसमें परिवर्तन करते जाते हैं। इस प्रकार के उत्तर न दें क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या बकायेदारों की बनी है। तो मुझे लगता है कि इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और इसलिए इसको प्रभावकारी बनाने के लिए क्या आमूल परिवर्तन करने की सरकार की मंशा है ?

महोदय, मैं दो-तीन सवाल पूछकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। आज उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में कितने मुकदमें लंबित पड़े हैं ? कितने दिनों से पड़े हैं ? आज तक जिन लोगों से आयकर की वसूली नहीं हुई उसमें चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो या बड़ी कंपनी का मालिक हो, क्या उनको कारावास हुआ है, हुआ है तो उसकी जानकारी क्या है ? जिस अधिनियम में यह प्रावधान है कि आप उनकी कुर्की कर सकते हैं, तो क्या उस अधिनियम के अंतर्गत आपने कुछ कार्यवाही की है, यह भी मैं जानना चाहूंगा।

इसके साथ जुड़ा हुआ एक और प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि जब आयकर बकाया रहता है तो व्यक्ति तो दोषी होता ही है, वह छोटा-बड़ा कोई भी हो वह दोषी है, वह कंपनी दोषी है। उसके साथ सख्ती बरती जानी चाहिये, इसमें दो राय नहीं हो सकती लेकिन उसके साथ-साथ आयकर विभाग के अधिकारी भी, मैं पूरे विभाग को तो दोष नहीं दे सकता क्योंकि बुराई और अच्छाई का इस प्रकार विश्लेषण नहीं किया जा सकता लेकिन आयकर विभाग के अधिकारी इनसे मिले होते हैं जिसके कारण यह बकाया बढ़ता जाता है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार की अपने ही विभाग के आयकर अधिकारियों पर नियंत्रण करने की क्या व्यवस्था बनी है जिसके कारण

आपकी मशा पूरी हो सके और जो बकायेदार चोर हैं वे इन अधिकारियों की वजह से बच न सकें। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या आज तक इन आयकर अधिकारियों पर कोई मुकदमे चले हैं ? अगर चले हैं तो कितने चले हैं ?

महोदय, आयकर अधिकारी जो होते हैं क्या उनकी आय उनके वेतन से ज्यादा है ? क्या इस दृष्टि से इसकी जांच की गई है कि उनके पास का पैसा उनकी कमाई से ज्यादा है ? तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के संबंध में सरकार किस प्रकार कदम उठा रही है ?

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि कर न देना दुर्भाग्य से एक राष्ट्रीय स्वभाव बन रहा है और अगर ऐसा स्वभाव देश का बन जाए और इस प्रकार की सुरक्षा उन लोगों को मिलती रहे तो मैं समझता हूं कि इससे सारी व्यवस्था के लिए एक प्रश्नचिह्न खड़ा होता है। वह नैया कभी तैर नहीं सकती जिसमें अनगिनत छेद हों। इसलिए इन छेदों को मिटाने के लिए सरकार विस्तृत रूप से क्या कर रही है, यह जानकारी वित्त मंत्री दें, यह मैं प्रार्थना करना चाहता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : The Minister will reply and after his reply, other hon. Members will be called to speak.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : Sir, earlier, in reply to Starred Question No. 103, I had stated the total amount of income-tax arrears that are outstanding as on 30th November, 1992, was Rs. 6,517 crores and that is a provisional figure. The analysis of the demand is as follows.

Out of this, demands not fallen due amount to nearly Rs. 480 crores. Then, demands stayed by courts and tribunals—Rs. 888 crores. Demands in which instalments have been granted—about Rs. 195 crores. Demands claimed to have been paid, but pending verification, amount to about Rs. 135 crores. Demands covered by petitions for waiver of interest—about Rs. 175 crores. Demands disputed by tax-payers, but not formally stayed about Rs. 1,848 crores.

SHRI PRAMOD MAHAJAN : Do these demands include the notices given ?

SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY : I will come to that. While raising this discussion, the hon. Member used the term 'the real total amount' But the meaning of 'real' is not clear because the entire demand of Rs. 6,517 crores is a regular demand raised on completion of income-tax assessments and related proceedings.

About the ten top companies, the defaulters who are in arrears of income-tax, with your permission, Sir, I give the information.

1. V.S.T. Industries Limited (status—company)—demand as on 31-12-92—Rs. 186.49 crores. 2. Dunlop India Limited (company)—Rs. 78.18 crores. 3. Peerless General Finance and Investment Company Limited (status—company)—Rs. 59.67 crores. 5. Continental Construction Company Limited (status—company)—Rs. 46.86 crores. 6. J.K. Synthetics (company)—Rs. 46.75 crores. 7. Bhalaji Distilleries Private Limited (status—company)—Rs. 43.34 crores. 8. R.K. Agarwal (status—individual)—Rs. 42.40 crores. 9. Sanchayita Investments (status—company) —Rs. 35.14 crores. 10. Reliance Industries Limited (status—company) Rs. 32.36 crores. This information is as on 31-3-1993.

In regard to the top ten non-company cases, I give the following information :

1. R.K. Agarwal (individual)—his name is there in the earlier list also —Rs. 42.40 crores. 2. Vinod Kumar Didwania(individual)—Rs.32.09 crores. 3. Shukurbhai Narainbhai Bhakia (individual)—Rs. 30.39 crores. 4. Bhagwandas H. Agarwal (individual —Rs. 15.07 crores. 5. Hansraj Dakar (individual)—Rs. 14.02 crores. 6. Harisiddha (specific family trust—A.O.P.)—Rs .12.94 crores. 7. Lokumal Choithram Veramani (individual) —Rs. 12.07 crores. 8. Sudhir and Kapadia (individual )—Rs. 11.77 crores. 9. J. Dharma Teja (individual) —Rs. 10.19 crores. 10. Systems Communications (status—R.F.) —Rs. 10.11 crores. In all these cases, in the case of companies as well as individuals, we have taken action.

There is a long list of the steps taken by the Department. If you permit, I will pass it on to the hon. Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : If it is a long list, you can send it to the hon. Member, but you can give a list of the same to the House. Also, how many cases are pending in court..(*Interruptions*).

SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY : If you want, I will send it to all those who have participated in this discussion.

Coming to court cases, I agree with the hon. Member that a huge amount is locked up in litigation. The number of cases pending with CIT is more than 2 lakhs, ITAT more than 2 lakhs, High Courts 34000 and in Supreme Court 3000. The Finance Minister in his Budget speech has mentioned that for expeditious settlement of the litigation, Government expects to bring forward a legislation to set up a national court for direct taxes.

The hon. Member has alleged that stringent action is taken against small persons and not big persons. Sir, in the eyes of law all are equal, but definitely I agree with the hon. Member that in the existing law there are some loopholes. We have to do something. The Government is aware of this. We will come before the House, we will ascertain the opinion of the House and then we will certainly have a better legislation for plugging the loopholes, for speedy recovery of arrears and for speedy disposal of cases also.

He has raised some points about stock brokers. As you are aware, the Joint Parliamentary Committee on the securities scam is already investigating this issue. That is why I do not want to add anything to this at this stage. Also it is not possible to clearly ascertain whether there has been any impact of the securities scam on income tax and corporate tax collection, but under the existing laws we are doing our best and we are taking stringent action against the tax defaulters.

SHRI PRAMOD MAHAJAN : What about corrupt officers ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : He has asked about the nexus between income-tax officers and the assessees.

SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY : I do not say that all officers are corrupt. It is difficult to establish the nexus between the officer and the assessee. If he has any

specific case, we will try to examine the same and take action.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Shri Chaturanan Mishra. Kindly put pointed questions. It is a Half-an-Hour Discussion, it should not become one-hour discussion.

SHRI CHATURANAN MISHRA (Bihar) : Generally it happens to be so. It is the convention. What can I do ? उपसभाध्यक्ष महोदय, उस दिन जो इस सदन में चर्चा चली और यह पता चला कि सरकार जिनके पास सब से ज्यादा इनकम टैक्स का बकाया है उनका नाम देने में असफल रही तो इससे सरकार की प्रतिष्ठा पर बहुत धक्का लगा। हम लोग सब समझने लगे कि पता नहीं इस बात को सरकार क्यों छिपा रही है? ऐसा होने से क्या होता है कि गवर्नमेंट की पोलिटिकल इमेज कन्ट्री में बहुत खराब हो जाती है। अभी लगता है कि उस वक्त मंत्री महोदय के पास सूचना नहीं थी। इनके पास तो अफसरों की फौज है। ये इतना भी बता नहीं पाते हैं तो यह फौज किस काम के लिए रखे हुए हैं? कोई ऐसा तरीका निकालिये कि अगर आपके पास सीधे कोई करप्शन का चार्ज आता है, वित्त मंत्री के पास आता है और आप कुछ नहीं करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे मंत्री ऐसे हैं, इसलिए यह भुगतना पड़ रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग काम नहीं करते हैं, कोई इन्फारमेशन नहीं देते हैं, क्वेश्चन का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं और मंत्रियों को ब्रीफ नहीं कर सकते हैं तो वे किस मर्ज की दवा हैं ? इसमें सबसे बड़ी चिन्ता की बात यह है कि देश में पोलिटिकल इमेज बर्बाद होती है और यह गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के फैल्योर के कारण होता है। इससे हम बहुत चिन्तित हैं। मुझ को कहा गया कि इस तरह की फंगशनिंग इसलिए है कि शायद वित्त मंत्री को अधिकार नहीं है कि किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकें। बड़ी अराजकता है। इससे देश में अगर ऐसा है तो सदन को इस बात को जानना चाहिए ताकि प्रधान मंत्री से कहा जाए कि आपको इसलिए चुना है कि आप कार्यवाही कर सकें। इसलिए इसको साफ किया जाना चाहिए। पहला आश्वासन तो मैं यह चाहता हूं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि अगर बकाया है और बहुत ज्यादा है, अगर इस गरीब देश का इतना ज्यादा टैक्स बकाया रहे तो यह अत्याधिक चिन्ता की बात है। लेकिन यह बात सरकार ने स्पष्ट नहीं की है कि यह एक साल का बकाया है या पिछले कई सालों से यह बकाया चला आ रहा है। अगर साल पर साल ऐसा है तो यह बहुत ही चिन्ता की बात है, अगर किसी परटीकुलर ईयर का है तो वह सोचा जा सकता है क्योंकि हर साल अगर बकाया रहता है और सरकार इससे अवगत है, कानून में कोई दोष है तो फिर आप कोई उपाय क्यों नहीं करते है ? इस बकाया का क्या मतलब होता है ? अगर सरकार इस बात से अवगत है और कानून में कोई दोष होने के कारण गलती चलती रहती है तो आप कोई कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं ? आप फीगर दीजिये कि यह कितने साल का है।

तीसरी बात हम जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि कोर्ट में इतने केसेज चल रहे हैं। कोई दो लाख इधर हैं, 34 हजार हाई कोर्ट में हैं और तीन हजार या 485 सुप्रीम कोर्ट में हैं। इनको आपने क्यों पड़े रखा है। क्या इसका कोई उपाय नहीं है ? आप लोग यह नहीं करेंगे तो कौन करेगा ? क्या अगले चुनावों के बाद आप करना चाहते हैं ? इस बारे में आप सोच क्या रहे हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता है। इतने केसेज बाकी हैं तो कोई तरीका तो निकालिये कि कुछ हो सके। इसलिए हम सोच रहे हैं कि डिफरेन्ट लेवल पर आप आमूलचूल परिवर्तन करते रहिएगा, लेकिन कोई एक्जीक्यूटिव तरीका निकालिये जिससे इन

केसेज को डिस्पोज किया जा सके । अगर ऐसा हो सकता है तो आप टेम्परेरी बहाली करें, ला को एमेंड करके बहाली करें । अगर इस समय नहीं करेंगे तो कब करेंगे ? उस दिन चर्चा में यह बात भी आई थी कि जो विख्यात हर्षद मेहता हैं उन पर कोई 9 हजार करोड़ का बकाया है । लेकिन कितना बकाया है यह बताने में सरकार मौन व्रत रखे हुए हैं । मौन व्रत चलते हुए यह सब हो रहा है और आज भी मौन व्रत रखे हुए है । आप इस मौन व्रत को तोड़िये ।

**श्री प्रमोद महाजन :** यह मामला जे० पी० सी० में है ।

**श्री चतुरानन मिश्र :** जे० पी० सी० की बात हम नहीं कर रहे हैं । उस दिन यह सवाल उठा था, लेकिन जवाब नहीं आया । उसके बारे में भी हम चाहेंगे कि आप कुछ कहें ।

अंतिम प्रश्न मेरा यह है कि जो ऐसे फेडुलेंट लेटीगेंट्स है, यह जो कंपनीज हैं तो कंपनीज को गवर्नमेंट बहुत सही फैसिलिटीज देती है । आप एक्जीक्यूटिव पावर दे दीजिये ताकि वे अपना मुकदमा जल्दी आकर सेटल कर दें । हमको तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सी कंपनियों का मुकदमा बिना कोर्ट में गये हुए ही, अगर आप ऐसा करेंगे, तो सेटल कर सकते हैं । अगर गवर्नमेंट इसको एज ए होल करे क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो बिना सरकार की मदद के फंक्शन करे । इसलिये डिफरेंट लेवल पर उनके लिये एक्जीक्यूटिव सपोर्ट विदड्रा कर दीजिये और अगर कंसेशन को विदड्रा कर देंगे तो वह उस केस में लौटते रहेंगे, जाते रहेंगे तब तो कंपनी फेल कर जायेगी । इसलिये अगर आपका दिल साफ है और दिमाग से काम लेना चाहें तो कोई वजह नहीं है कि गरीब देश की इतनी भारी रकम आपकी रहे और आप हाथ पसार पसार कर कर्जा मांगते चले जाए, जगह जगह पर कि हमें और कर्जा दीजिये, हमको और कर्जा दीजिए । आज हम इसको लेने में दुनिया में फर्स्ट हो रहे हैं । इसलिए आप कम से कम जरा देश की इज्जत बचाइये, यही मुझे आपसे कहना है । धन्यवाद ।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN (Madhya Pradesh) : Just now the hon. Minister has said that an amount of more than Rs. 65.20 crores is lying as arrears of income-tax. Our Minister is a doctor. I am also a doctor. Everybody knows that I am a real doctor. But, he is a big doctor. There is a saying that....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Dr. Jain, there are so many doctors in this House.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN : No. We are talking only about the proverb, 'Doctor, heal thyself,' I would like to know how much of income-tax and wealth-tax arrears is to be recovered from the Cabinet Ministers ? Then related to this question is how much of income-tax and wealth-tax arrears is to be recovered from the Members of Parliament ?

SHRI CHATURANAN MISHRA : Do you want another Half-an-Hour Discussion ?

DR. JINENDRA KUMAR JAIN : One of the problems of the Indian society is the nexus between the politicians and the rich industrialists. We all know about it. But the question is whether there is the will of our Government and the system to deal with this problem effectively. Everybody knows that there are income-tax arrears in the film industry. But people also know that such film stars, when they become Members of Parliament and if they are Members of the ruling party, they are spared. There is a very famous case of a film star in Bombay, a great

hero of this country and the film world and a member of the ruling party. He was a hero. There was a producer who had given him the fees. All the cases were put up against the producer, who gave money to the hero. He was asked how much money he had paid to him. But nobody was authorised to put any question to that hero, because he was a member of the ruling party. What I want to say is that if politicians, whether they are Ministers or Members of Parliament, secure some kind of immunity from that kind of scrutiny, then we cannot deal with this problem effectively. That is why I said that we need to set our own house in order so that we can deal with it. The Finance Minister is fond of saying that income-tax evasion is a world-wide phenomenon. Let us see how other countries deal with the situation. The Minister has returned from America only last week. He knows the case of a famous lady who owns a number of hotels in America. This lady was found to have done a small tax evasion. It was a big amount, but small for her. She had put her swimming pool expenses, which she incurred for her own private swimming pool, into the account of her hotel swimming pool. And for it the lady had to pay one hundred million dollars as penalty. Yet the Government has not spared her. She is lying in jail. The moment you talk of tax-evasion system in that country, everybody refers to that. The value of the exemplary punishment is great while dealing with the problem.

Do we have any story of exemplary punishment in this country ? Just now the hon. Minister had mentioned about the top ten corporations who are in arrears of income-tax and also about the corporation which is heading as number one in the list. There was another question in this House sometime back, "Who are the top ten industrial house evading excise duty ?" He had mentioned about an industrial house which was topping the list of evasion of excise duty. The current issue of *India Today* carries a two-page feature on the same industrial house, the same group is having an offshore company in the British Channel Island. According to this write-up, more than a thousand crores of rupees of investment has been made by this group in that country. Is there nobody in this country to ask that Indian industrial house, "How did you manage to carry this amount in foreign exchange to a foreign country ? How did you manage to acquire huge money in foreign exchange and invest it in a foreign country ?" I am not talking how he had earned that money. Every day newspapers give the *havala* rates. Today the *havala* rate has gone up between Rs. 8 and Rs. 9. It was more than the official rate. Is it not true that the Government of India does not know about this ? Does the present Finance Minister have the political will to deal with this problem squarely ?

Since you have asked me to conclude, I will end my brief statement by making only the last query. He says that corruption cases against the Income-tax officials are admitted. But they do not know the specific case. May I know from the Minister whether he is willing to give an assurance here that if Members of Parliament bring specific cases of corruption against the Income-tax officials, he will take action ? I know of cases where with impunity, the income-tax officials say, "We know nobody. It is a matter of principle. Without taking money,

we will do nobody's work". The rules are such that everybody is a thief in this country. There is a need to improve the rules so that they are not heavily loaded against tax-payers. Today what is happening is that because of such faulty rules, an honest tax-payer is at the mercy of corrupt Income-tax officials; and the tax-evaders have their day.

Please allow me only one sentence more. Judicial delays have been cited as one of the examples of income-tax arrears. I know that most of the Income-tax Tribunals are now manned by the Government officials themselves. They give repeated adjournments in the Tribunal. The quality of the lawyer engaged by the income-tax evaders is different from the quality of lawyer engaged by the Government to defend the Government's money because the interest money to be paid on the income tax arrears can enable the evaders to hire the best lawyers.

Who will defend people's money ? That is my question. Thank you.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I have only two or three pointed queries. Actually in the process of collection of income-tax, what is the difference between an assessment and the dues ? When do you call it as an assessment ? When does it become dues ? There are two or three words in the income-tax usage. The first one is an assessee. The second one is a defaulter. According to Mr. Mahajan, when does he become a *doshi* ? There should be a clear demarcation. An assessee may not be a *doshi*. Even the defaulter may not be a *doshi*. A person seeking permission from the Income-tax authorities to pay the income-tax arrears in instalments or who is challenging the assessment may not be a *doshi*. Who is not a *doshi* ? Unfortunately, Mr. Mahajan has dubbed all of them as *doshis*. *Doshi* is a Hindi word.

SHRI CHATURANAN MISHRA: It is not Joshi.

SHRI H. HANUMANTHAPPA : Not Joshi but *doshi*. He had clubbed all these things. We want to know what is the difference between an assessee, a defaulter and a *doshi* ?

Let not an honest assessee also be clubbed with a 'doshi'. That is why I want a clarification on that.

There is one more thing, the percentage of the cost of collection of arrears. The Ministry formed a Committee. The Committee gave a report about augmenting staff etc., but, unfortunately, action has not been taken on this report. You insist upon a certain percentage on the recovery. If you just increase the charge by half a per cent or one per cent, for augmenting staff, a lot of collections can be made. There are reports in the Ministry. Kindly look into them. You have created posts at higher levels. But the supporting staff have not been given. When we, a Committee, went to inspect the offices at various places, we came to know that higher posts had been created, promotions had been given, but supporting staff had not been created. There are a number of vacancies in various departments. That also causes delay in the collection of arrears.

Then, you have mentioned about establishment of a national court. This recommendation is pending before the Ministry and the Government for the last about five years. A Committee was formed under the chairmanship, convenorship, of Shri Virendra

Patil by late Shri Rajiv Gandhi when he was holding the finance portfolio and its recommendation is still lying with the Government. Will the Minister tell us when this Bill, which gives you power, authority, to collect the arrears and augment the resources of the Government, will come before the House ?

Lastly, can a medical doctor also indulge in film production, video production ? Is there any exemption if he is a Member of an Opposition party ? Does it not attract tax ? Is he paying double professional tax? Has this point been taken note of by the Ministry ?

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar) : Mr. Vice-Chairman, Sir, since many questions have been already asked on many aspects, I am not going into them. I would just like to have only two or three clarifications from the Minister.

The Minister, in his reply, has given some information about tax evasion, how many cases are pending before the Courts, before the Supreme Court and the High Courts, and their total number. I would also like to know whether there are any habitual defaulters in the cases that he has cited. If so, who are the habitual defaulters and what does the Government propose to do with them ? What will be the plans of the Government and how soon will the Government take action against them ? How soon will the Government dispose of the pending cases ? It is really ridiculous that you spend more money on the litigation itself than the amount you seek to recover. So, will the Government make the process simpler and try to recover the money as soon as possible ?

Thank you, Sir.

**श्री सतीश प्रधान** (महाराष्ट्र) : थैंक्यू वाइस चेयरमैन सर। मैं दो ही सवाल पूछना चाहता हूं । पहली बात ऐसी है कि हमारा प्रेक्टिकल एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम जब लोगों के पास से इन्कम टैक्स वसूल करने के लिए कोशिश करते हैं तो बहुत सारे केसेज में लोगों के बैंक एकाऊंट में जितना भी पैसा फोर्स से आता है उनका जो इन्कम है, जैसे कंट्रेक्टर है, कंट्रेक्टर का पैसा है उसके एकाउंट में आ जाता है तो वह उसको वेजेज के लिए भी नहीं दिया जाता है, वर्कर्स को वेजेज देने के लिए भी नहीं देते हैं । वह भी पैसा हमारे यहां एकाउंट में ले लेते हैं इन्कम टैक्स वसूल करने के लिए । ऐसा एक्सपीरियंस है काफी जगह पर । छोटे-छोटे कंट्रेक्टर आदि लोगों के बारे में इस ढंग का आपका वास्ता पड़ता है लेकिन ये जो बड़ी-बड़ी मालदार पार्टीज हैं जो नाम आपने बताये, वहां ऐसा ही बर्ताव आपकी तरफ से क्यों नहीं होता है ?

6.00 P.M.

दूसरी बात यह है कि लिटिगेशन में बहुत से केसेज हैं । तो कोर्ट में केस जब जाता है, मैं ऐसा मानता हूं कि किसी को भी आपके खिलाफ कोर्ट में जाना है, तो उसको जो भी कुछ टैक्स का पैसा है, वह उसे पहले कोर्ट में डिपाजिट करना पड़ता है । ऐसा मेरा ख्याल है ।

तो वह जो पैसा पहले उधर डिपाजिट किया जाता है, वह सस्पेंस एकाउंट में रखेगा, तो वह कैसे होगा । वह पैसा जो भी कुछ प्रोग्राम के लिए युटिलाइजेशन में ला सकते हैं, वह नहीं ला सकते ।

मेरे सिर्फ यही दो सवाल हैं । धन्यवाद ।

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu) : Mr. Vice Chairman, Sir, I must thank you for giving me this opportunity. I want to put one question to our Finance Minister. A Chief Minister, who says she is

getting a pay of only Re.1, is now an income-tax assessee one who has defaulted for six years and for paying that she has taken time also. How has this thing happened ? She is getting only Re. 1. That is her assessment and she has also publicity stated, "I am the only Chief Minister who is getting only Re. 1 per month". How then is it that she comes under income-tax ? As regards the arrears, after an hon. Member raised the issue in the House, the income-tax authorities woke up from their slumber and then they say, "Yes, she has to make the payment". Then she says, "I will pay that amount". I would like to know whether such persons are guarded by the Government and who the official is who is protecting such persons and whether the Government is hand-in-glove with the Chief Minister.

SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY : Sir, hon. Member, Mishraji, has raised a point that arrears were bogged down in litigation and we had to do some improvements in the legislation so that there would be speedy disposal of the cases at the department level as well as at the court level. Anyway, I have already said that the Government is making all efforts to plug the loopholes in the existing Income-tax Act to recover the arrears speedily and to dispose of the cases speedily. In addition to that, for speedy disposal of the cases, the Government is going to come before this House with a legislation to constitute a national court for direct taxes. We will come before this House soon. He has mentioned about the share-brokers of Bombay who were involved in the scam. But, as I have already said, this securities scam is being investigated by the JPC. I don't want to add anything at this stage.

Hon. Member, Dr. Jain, wanted to know about the income-tax and wealth-tax returns filed by Cabinet Ministers and also by Members of Parliament. For this I need a separate notice because this question does not come within the ambit of the earlier starred question which I answered.

SHRI PRAMOD MAHAJAN : Nobody is there in the first ten.

SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY : He has suggested exemplary punishment for the defaulters. Sir, even under the present Income Tax Law we have sufficient provision. We are making use of that. He also raised one more point. If any specific case of corruption is pointed out by any hon. Member, we will definitely examine it and take action. Mr. Hanumanthappa has mentioned about assessments, dues and defaulters. I wish to add that as soon as an assessment is made, the demand is raised. It must be paid within 30 days under the existing Income Tax Act. Even if the demand is disputed in appeal, still it is shown as arrears unlike the Central Excise Act. This provision is available in the Income Tax Act. The Government has made very sincere efforts in getting the arrears. As on 1-4-1992, it was Rs. 8467 crores. As on 30th November, 1992, it was reduced to Rs. 6517 crores. It was further reduced to Rs. 6343 crores as on 28 February, 1993. The hon. lady Member has asked whether we have identified any habitual defaulters. We have no such mechanism under the Income Tax Act. We are making very sincere efforts to clear all to pending cases as early as possible.

Mr. Satish Pradhan wanted to know, in the case of non payment of income tax by small contractors,

whether their bank accounts will be frozen. It is not a question of small contractors or big contractors. We are doing it in the case of big contractors also. Mr. Venkatraman was referring to some Chief Minister. I don't know which Chief Minister he was referring to.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN : The present Chief Minister of Tamil Nadu.

SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY : I wish to inform the hon. House that there are no income tax or wealth tax arrears outstanding against the Chief Minister. However, income tax and wealth tax assessments for the assessment years 1987-88 onwards are pending before the Department.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN : It was pointed out by one hon. Member of this House. Then the Income tax Department started working. She has given an explanation that she is an agriculturist and inadvertently she has not paid the income tax. All these things were there in the newspapers also. How is it that she has been relieved from the income tax net ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : You are asking a specific qustion. The discussion is on a general subject. He needs a separate notice for that. The discussion on this subject is over now.

---

## SPECIAL MENTIONS—Contd.

### Need to Complete the Upper Krishna Irrigation Project

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I seek your permission to make a mention on a very important matter regarding implementation of an irrigation project which affects the lives of lakhs of people. The Bachawat Water Tribunal had allotted a share of 734 TMC for Karnataka to be utilised before the end of the century. Several projects which were taken up in this river valley basin so far have not been able to utilise 460 TMC of water covering 14.70 lakh hectares whereas the total capacity is 30 lakh hectares leaving a balance of 16 lakh hectares to be brought under irrigation by utilising 274 TMC of water from Krishna. The cost of these projects so far incurred by the Karnataka Government is Rs. 2,132 crores and the Karnataka Government requires a further sum of Rs. 3,182 crores as of date for completion of these projects. Taking the escalation cost even at a modest rate of 10 per cent every year, the cost will go up to Rs. 6,000 crores which the State Government is not in a position to allocate within its resources. Therefore, irrigation of 15 lakh hectares which gives a livelihood to lakhs of people is becoming a dream. Therefore, there is an urgent need for finding alternative arrangements for taking up and completing the irrigation project which started as early as 1963. This will go a long way in improving productivity besides giving employment to lakhs and lakhs of people in this area. I therefore, urge upon the Centre to take up this project as a Central project as in the case of Narmada Project wherein the Government of India readily agreed to invest Rs. 1,300 crores, even rejecting the World Bank's loan for completion of the project. Therefore, I appeal to the Central Government to take over this Upper Krishna Project which is pending for more than 30 years and which